वृद्धि संवेग की पुन: प्राप्ति: मुद्दे और चुनौतियाँ*

के. सी. चक्रवर्ती

श्री प्रतीप चौधरी, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; डॉ. राजन सक्सेना, कुलपति, नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआइएमएस); डॉ. देवाशीष सान्याल, डीन; डॉ.वृंदा कामत, चेयरपर्सन (एमबीए बैंकिंग); श्री सी. बी. रामामूर्ति, बैंक ऑफ बड़ौदा के मेरे पूर्व बॉस; स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, एनएमआइएमएस विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य और छात्र; प्रतिष्ठित अतिथि गण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य गण, देवियो और सज्जनो! सबसे पहले मैं इस संस्थान को बधाई देता हूँ कि उसे बिजनेस वर्ल्ड द्वारा चौथा सर्वोत्तम बी स्कूल घोषित किया गया है और मैं क्रिसिल द्वारा ए*** श्रेणी निर्धारित किये जाने पर भी संस्थान को बधाई देता हूँ। मैं विश्वविद्यालय की इस बात के लिए सराहना करता हूँ कि यह छात्रों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते हुए राष्ट्र की भी उत्कृष्ट सेवा कर रहा है।

2. वस्तुतः मेरे लिए यह हर्ष का विषय है कि मैं आज की प्रातःबेला में छठे वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन 'बैंक ऑन इट 2013', जो एनएमआइएमएस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया है, में आरंभिक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज प्रबंधन के क्षेत्र के उदीयमान पेशेवर व्यक्तियो के बीच, जो कल के कारपोरेट अग्रणी बनेंगे, अपने को पा कर मैं प्रफुल्लित अनुभव कर रहा हूँ। इस सम्मेलन में अतीत में कुछ वक्ताओं को आमंत्रित किया जा चुका है, जिन्होंने विविध प्रकार के संगत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया, जो बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि संस्थान ने इस वर्ष के सम्मेलन के लिए विषय-वस्तु के रूप में ''विपत्ति के बीच वृद्धि को बनाये रखना'' को चुना है, एक ऐसा विषय, जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि-संवेग में गिरावट के बारे में व्यापक चिंताओं पर विचार करते हुए सर्वाधिक संगत है। भारत की वित्तीय प्रणाली के अंतरंगी के रूप में, पहले एक वाणिज्यिक बैंकर के रूप में और बाद में केंद्रीय बैंकर के रूप में मैं आज इस प्लैटफार्म का उपयोग भारत की वृद्धि, उद्यम, अभिशासन, आदि के बारे में अपने विचारों को आपसे साझा करने के लिए करना चाहता हूँ और इस पर विचार करना चाहता हूँ कि उच्च वृद्धि के प्रक्षेप-पथ पर फिर से लौटने के लिए और वृद्धि को बनाये रखने के लिए क्या कुछ करना आवश्यक है। इस विषय पर छात्रों के साथ बातचीत करना बहुत प्रेरणास्पद है, क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति हैं, जो आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के 'जनित्र' और प्रकाश-स्तंभ बनने वाले हैं।

3. हम सभी इस समय वृद्धि के संबंध में किये गये भिन्न-भिन्न पूर्वानुमानों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे भारत चालू वर्ष में प्राप्त कर सकता है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा कारक लागत पर वास्तविक जीडीपी में वृद्धि के लिए किये गये पूर्वानुमानों का दायरा (मीडिया में उद्धृत) 4.25 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत के बीच है। कोई इस बात को महसूस कर सकता है कि आरबीआई द्वारा और किसी अन्य संस्था द्वारा किये गये वृद्धि संबंधी पूर्वानुमान सांकेतिक हैं और कतिपय धारणाओं पर निर्भर करते हैं। हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग अपने घरों में हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें और पूर्वानुमानित वृद्धि दर प्राप्त हो जाये। लोगों में एक सामान्य भ्रांति यह है कि अर्थव्यवस्था की सारी बीमारियों को आरबीआई या वित्तीय प्रणाली द्वारा ठीक किया जा सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि वित्तीय प्रणाली अपने आप वृद्धि की प्रक्रिया को तेज नहीं कर सकती; यह केवल संपदा क्षेत्र को वित्त प्रदान कर आर्थिक वृद्धि को सुविधाजनक बना सकती है। धारणीय वृद्धि के लिए बुनियादी प्रेरक शक्ति को अनिवार्यतः संपदा क्षेत्र से उत्पन्न होना होता है। हम सभी अब यह जानते हैं कि वैश्विक वित्तीय संकट के मूल में अत्यधिक वित्तीय नवोन्मेष और वित्तीय क्षेत्र का संपदा क्षेत्र से बहुत आगे बढ़ जाना रहा है। इसलिए, संपदा क्षेत्र की समस्याओं का हल निकालने के लिए वित्तीय क्षेत्र पर पूर्ण निर्भरता होना और वृद्धि प्रक्रिया में तेजी लाना अयथार्थवादी विचार होगा।

परिचय

4. आज की चर्चा के विषय, अर्थात्, 'विपत्ति के बीच वृद्धि को बनाये रखना' , पर लौटते हुए, मैं सोचता हूँ कि यह अधिक प्रासंगिक होता, यदि इसे 'विपत्ति के बीच वृद्धि में सुधार करना' कहा गया होता। आप ध्यान दीजिए कि संकट ने वैश्विक तौर पर सभी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया। हमारे लिए स्वयं को

* 5 अक्तूबर 2013 को मुम्बई में नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा आयोजित छठे वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन 'बैंक ऑन इट'' में डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में दिया गया भाषण। श्री अरुण विष्णु कुमार द्वारा दी गयी सहायता को कृतज्ञतापूर्वक अभिस्वीकार किया जाता है।

इस दलदल से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहला काम यह किया जाना है कि हम सकारात्मक सोच रखें और दोष मढ़े जाने का खेल बंद कर दें। केंद्रीय बैंक, बैंकों, नीति-निर्माताओं, सरकार, आदि को संकट के लिए दोष देने से कोई मदद नहीं मिलेगी। हमारा प्रारंभिक उद्देश्य होगा इस बात का विश्लेषण करना कि पहले तो यह संकट आया क्यों, अथवा, अधिक सामान्य रूप में कहें, तो क्यों विपत्ति आघात करती है? सच में, इसके अनेक कारण बताये जाते हैं, कुछ आर्थिक स्वरूप के होते हैं, तो कुछ सामाजिक और कुछ राजनीतिक स्वरूप के होते हैं। लेकिन सभी संकटों के लिए एक सामान्य कारण होता है सद्गुण या अनुशासन में हर तरह से कमी आना। यहाँ मैं भगवान कृष्ण की भगवद्गीता के अध्याय 4 में कही गयी उक्ति का निवेदन करना चाहता हूँ, वे कहते हैं :

''यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्?
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे?''

इस कविता का अर्थ यह है कि ''जब कभी और जहाँ कहीं धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्कर्ष होता है, उस समय मैं अवतार ले कर धर्मपरायण लोगों को विपत्तिमुक्त करता हूँ और अधर्मियों का विनाश करता हूँ, तथा धर्म के सिद्धांतों को पुनःस्थापित करता हूँ। मैं स्वयं युगों युगों तक अवतार लेता हूँ।''

5. यदि हम इस तर्क का विस्तार करते हुए वित्तीय क्षेत्र में संकट की स्थिति के सृजन से जोड़ें, तो हमारा निष्कर्ष यह हो सकता है कि वित्तीय संकट प्रणाली में भ्रष्ट, अकुशल और कपटपूर्ण तत्वों को निकाल बाहर करने के लिए घटित होता है, जिन्हें सामान्य समय में उत्तम विनियमों, उत्तम नीतियों और उत्तम कारपोरेट अभिशासन के द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। तथापि, ज्वलंत तथ्य यह है कि ऐसे परिमाण वाले संकट जीवन में एक ही बार आते हैं। इस संकट से उबरने और उच्च वृद्धि के पथ पर आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक होगा कि हम उत्तम गुणों का विकास करें और गलत प्रथाओं- अनुशासनहीनता इनमें से एक है, को समाप्त करें। हमें अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक भूमिकाओं में अधिक अनुशासनबद्ध होना होगा, कार्यपरक जीवन में अधिक पारदर्शी बनना होगा, बर्बादी रोकनी होगी, कठोर परिश्रम करना होगा, उत्पादकता और कुशलता बढ़ानी होगी और कौशल उन्नयन करना होगा।

हमारी संभाव्य वृद्धि क्या है?

6. अब मैं विषय-वस्तु के आर्थिक पहलू की ओर आता हूँ। विषय का पहला भाग 'वृद्धि को बनाये रखना' यह प्रश्न सामने रखता है, 'हम किस प्रकार की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना और उसे बनाये रखना चाहते हैं?' यह हमें 'संभाव्य वृद्धि' के मुद्दे की ओर ले जाता है। 'भारतीय अर्थव्यवस्था की संभाव्य वृद्धि दर क्या है?' यह प्रश्न शिक्षा जगत और नीतिगत अनुसंधान के क्षेत्र में सक्रिय वाद-विवाद का विषय रहा है। संभाव्य उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए अनेक कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दे होते हैं। मोटे तौर पर कहा जाये, तो दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, वृद्धि लेखांकन दृष्टिकोण और सांख्यिकीय निस्यंदन तकनीक। अनुमान लगाने की भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ अलग-अलग परिणाम देती हैं, जिसके चलते काफी अनिश्चितता का सृजन होता है। पुनः, भारतीय संदर्भ में, प्रासंगिक आँकड़ों के अनुपलब्ध होने से अनुमान लगाने की समस्या गंभीर हो जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अभिप्रेत/संभाव्य वृद्धि दर, जो वर्ष 2005-06 से लेकर 2007-08 तक औसतन 8.5 प्रतिशत पर थी, वह उसके बाद धीरे-धीरे कम होती गयी और इस समय लगभग 7 प्रतिशत पर है। प्रारूप पंचवर्षीय योजना (2012-17) दस्तावेज में यह इंगित किया गया है कि हमारी पूर्ण संभाव्य वृद्धि लगभग 9 प्रतिशत पर है। इन संख्याओं का संदर्भ प्राप्त करने के लिए मैं वर्ष 1951-52 से भारत के वृद्धि संबंधी अनुभव का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता हूँ।

भारत की वृद्धि-यात्रा-सार संक्षेप

7. आजादी के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि की कहानी एक दिलचस्प अध्ययन है। हम वर्ष 1950 से लेकर तिरेसठ वर्षों तक भारत की वृद्धि को पाँच प्रमुख चरणों में निर्धारित कर सकते हैं (सारणी 1 और चार्ट 1)। जैसाकि आप सभी जानते हैं, पहला चरण 'न्यून वृद्धि' अवधि[1] के साथ-साथ चलता है। पहले चरण के दौरान, 1951-52 से 1979-80, औसत वास्तविक जीडीपी 3.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी और प्रति व्यक्ति आय में 1.3 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई, जिसे तथाकथित 'हिन्दू

[1] पहले चरण के समाप्त होने की तिथि के बारे में अभी भी बहस चल रही है। अनेक अर्थशास्त्री अब यह तर्क देते हैं कि अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि के पथ पर वर्ष 1980-81 में अग्रसर हुई, जो 1990 के दशक के प्रारंभ में व्यापक संरचनात्मक सुधारों को आरंभ किये जाने के एक दशक पूर्व है।

वृद्धि दर''[2] कहा गया। वृद्धि का मुख्य चालक था घरेलू उपयोग। निवेश-दर न्यून थी और उसका अधिकतर वित्तपोषण घरेलू बचत द्वारा किया जाता था और इस प्रकार चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी के 1 प्रतिशत से कम था। इस चरण के दौरान वृद्धि की अगुआई औद्योगिक क्षेत्र ने की, जिसके बाद सेवा क्षेत्र का स्थान है (सारणी 2)।

8. वृद्धि में तेजी दूसरे चरण (1980-81 से 1993-94) के दौरान आयी। 1980 के दशक के दौरान वद्धि में तेजी अनेक कारकों के चलते आयी, जिनमें 1980 के दशक के दौरान औद्योगिक और व्यापार उदारीकरण के लिए आरंभिक प्रयास करना, सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी, सभी तीन क्षेत्रों का बेहतर कार्य-निष्पादन और एक उत्तरोत्तर विस्तारवादी राजकोषीय नीति शामिल थी (केंद्र का राजस्व घाटा और पूँजीगत व्यय, दोनों ही 1980 के दशक में जीडीपी के अनुपात के रूप में बढ़े)। घरेलू बचत की तुलना में निवेश में अधिक वृद्धि होने से, सीएडी में बढ़ोतरी हुई। वृद्धि के तेज होने से डब्लूपीआइ मुद्रास्फीति भी बढ़ी।

9. तथापि, 1980 के दशक की वृद्धि-प्रक्रिया उत्तरोत्तर अधारणीय बनती गयी, जैसाकि इस दशक में उच्च राजकोषीय घाटा, उच्च स्तर का सीएडी, और बढ़ते बाह्य ऋण के अतिरिक्त निरोधक एवं दुर्बल होती वित्तीय प्रणाली के रूप में बढ़ते समष्टिआर्थिक असंतुलनों में अभिव्यक्त होता है। इन असंतुलनों की पराकाष्ठा वर्ष 1991 के अभूतपूर्व बाह्य भुगतान संकट में दिखाई दी, जिसका प्रबंध स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत से किया गया।

10. अर्थव्यवस्था में वर्ष 1993-94 के आसपास स्थिरता आयी और वृद्धि में पुनः तेजी आयी। तथापि, तीसरे चरण (1994-95 से 2002-03) में देखी गयी अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि का अंत वर्ष 2002-03 में हो गया, जब अर्थव्यवस्था में गंभीर सूखे की स्थिति का प्रभाव पड़ा। निवेश और बचत दर में बढ़ोतरी हुई और सीएडी थोड़ा कम हुआ। मुद्रास्फीति भी कम हुई। अगले पाँच वर्षों में अर्थव्यवस्था में उछाल आया (चौथा चरण : 2003-04 से 2007-08), जिसमें निवेश में वृद्धि के साथ 9 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की गयी। निवेश की तुलना में घरेलू बचत के बढ़ने से सीएडी में और कमी हुई। मुद्रास्फीति भी सौम्य बनी रही। राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित किये जाने से राजकोषीय घाटे को भी नियंत्रित किया गया। यह अवधि संभवतः भारत की वृद्धि के इतिहास में 'स्वर्णिम अवधि' थी और फलतः इसने इस प्रकार के वाद-विवाद को बढ़ावा दिया कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था 'हाथी से शेर' बन गयी है?[3]

11. भारतीय अर्थव्यवस्था 2005-06 से 2007-08 तक की तीन वर्षीय अवधि के दौरान 9.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो संयत मुद्रास्फीति, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और बचत एवं निवेश में तेजी द्वारा समर्थित हुई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी तीन वर्षीय अवधि के दौरान यह सबसे ऊँची वृद्धि दर थी और उस अवधि के दौरान यह प्रमुख देशों के बीच केवल चीन की तुलना में दूसरे स्थान पर रही थी।

12. भारत की उच्च वृद्धि की कहानी संभवतः समय से पहले रुक गयी, जिसका कारण था वर्ष 2007-08 का वैश्विक वित्तीय संकट (वास्तविक जीडीपी वृद्धि कम होकर 6.7 प्रतिशत हो गयी)। उस समय समष्टिआर्थिक नीति में ध्यान संसर्ग को रोकने से पुनःप्राप्ति का प्रबंध करने की ओर दिया गया। अर्थव्यवस्था में वर्ष 2009-10 में उछाल आया (8.6 प्रतिशत) और वर्ष 2010-11 में (9.3 प्रतिशत)। समन्वित राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था की पुनःप्राप्ति में और वित्तीय बाजार की स्थिरता बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उसके बाद से वृद्धि-संवेग कम होने लगा, जिसके चलते वर्ष

[2] प्रोफेसर राजकृष्ण हमारे वृद्धि संबंधी कार्य-निष्पादन की अपर्याप्तता की ओर निश्चित ध्यान आकृष्ट करने वाले लोगों में से एक थे, जब सत्तर के दशक के मध्य में उन्होंने बहुधा उद्धृत वाक्यांश 'हिन्दू वृद्धि-दर' गढ़ा, जो भारत की निराशाजनक अभिप्रेत वृद्धि बताने के लिए था। मोंटेक सिंह अहलूवालिया (1995)। ''इकोनॉमिक रिफार्म्स फॉर दि नाइन्टीज'', जो राजस्थान विश्विद्यालय में अप्रैल 1995 में प्रथम राजकृष्ण मेमोरियल लेक्चर के रूप में दिया गया व्याख्यान था, जिसे योजना आयोग के वेबसाइट http://planningcommission.gov.in/speech/spemsa/msa033.pdf से लिया गया है। तथापि, साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है, जो यह बताये कि 'हिन्दू वृद्धि दर' किसी भी लिहाज से हुन्दू धर्म से स्वयं संबंध रखती है... जिसका अधिकतर संबंध समाजवाद के भारतीय रूपांतर से रहा'' (विरमानी (2004) ''इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ : फ्रॉम सोशलिस्ट रेट ऑफ ग्रोथ टू भारतीय रेट ऑफ ग्रोथ'' वर्किंग पेपर नं.122, आइसीआरआइईआर, फरवरी 2004)।

[3] चक्रवर्ती, के.सी. (2013); ''ट्रांजिट पाथ फॉर इंडियन इकोनॉमी : सिक्स स्टेप्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दि एलीफैंट टू टाइगर.' इस बहस का प्रांजल प्रतिपादन करता है।''http://rbi.org,in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=13912।

2011-12 में वृद्धि दर घट कर 6.2 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 5.0 प्रतिशत हो गयी और चालू वर्ष 2013-14 में पूर्वानुमान किया गया है कि वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रहेगी। सेवा क्षेत्र, जो भारत की उच्च वृद्धि का चालक रहा था, में भी गिरावट आयी। वैश्विक समष्टिआर्थिक और वित्तीय अनिश्चितता, दुर्बल बाह्य माँग, उत्थित मूल्य स्तर, दोहरे घाटे का विस्तार और गिरते निवेश ने मिल कर वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

13. यह भी याद रखा जाना चाहिए कि पिछले वर्षों में प्राप्त उच्च वृद्धि के चलते सामान्य रूप से लोगों की आकांक्षा बढ़ गयी है और कोई भी 5.5 की वृद्धि दर से खुश नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि, यद्यपि हर कोई वृद्धि को 9 प्रतिशत से अधिक दर से बढ़ते हुए देखना चाहता है, फिर भी इसे प्राप्त करने के लिए कोई पसीना बहाने (कठोर परिश्रम करने) को तैयार नहीं है। हमारा समाज समृद्ध हो, इसके लिए हमें निकट भविष्य में निरंतर 9 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करना होगा, और इसके लिए संपदा क्षेत्र को सुसंगत रूप से बढ़ना होगा। इसे केवल उत्पादकता और दक्षता बढ़ा कर और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आपके जैसे उदीयमान पेशेवर व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक है कि वे क्षेत्र में जायें और ऐसी प्रणालियाँ स्थापित करें, जो लोगों में अभिलाषा जगाने और उन्हें पसीना बहाने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि संभाव्य वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

हमने शेष विश्व की तुलना में कैसा काम किया ?

14. हम दुनिया में सबसे अधिक तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहे हैं। यह 1980 से क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के संदर्भ में विश्व-जीडीपी में भारत के बढ़ते हिस्से से पता चलता है (चार्ट 2)। जैसाकि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, जो चुनौतियाँ इस समय हमारी अर्थव्यवस्था को झकझोर रही हैं, वे भारत के लिए विशिष्ट नहीं हैं। पूरे विश्व में कई देश मंद वृद्धि दरों की समस्या से जूझ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से बढ़ते एकीकरण का एक अवांछित परिणाम यह हुआ है कि हम वैश्विक आर्थिक वृद्धि प्रवृत्ति से अब वियोजित नहीं रहे हैं। वैश्विक रूप से आर्थिक वृद्धि की वर्तमान न्यून दर ने भी उच्चतर वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त करने के हमारे मिशन को बाधित किया है।

वर्षों से हमारी ताकत क्या रही है?

स्पंदनशील प्रजातंत्र ने भारत को समुत्थानशील बनाया है

15. भारतीय संविधान को अपनाये जाने के समय से भारत एक स्पंदनशील प्रजातंत्र बना रहा है, यही हमारी ताकत रही है। स्वतंत्रता के बाद पैंसठ वर्षों से अधिक समय तक देश ने अनेक विपत्तियों का सामना किया है, बाहरी आक्रमण और आरंभिक वर्षों में अकाल पड़ना, कुछ वर्ष सूखा पड़ना, 70 के दशक का तेल संकट, 90 के दशक के आरंभ में बीओपी संकट, जिसके बाद 90 के दशक के अंत में आया दक्षिण-पूर्व एशिया संकट, वैश्विक वित्तीय संकट, जो अमेरिका के सब-प्राइम संकट के साथ शुरू हुआ और वर्तमान में यूरो क्षेत्र संकट। एक सपंदनशील प्रजातंत्र और हमारी समुत्थान शक्ति ने हमें सभी विपत्तियों पर विजय पाने में अब तक मदद की है। मुझे विश्वास है कि हम वर्तमान संकट से भी पार पा जायेंगे।

भारत में 9 प्रतिशत और उससे अधिक दर से बढ़ने की सक्षमता है

16. अपने वृद्धि संबंधी इतिहास और शेष विश्व की तुलना में अपने कार्य-निष्पादन को देखने पर, हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में यह क्षमता है कि यह 9 प्रतिशत और उससे अधिक दर से वृद्धि कर सकती है। अतः, इस समय हम अपनी संभाव्य वृद्धि से न्यून दर पर वृद्धि कर रहे हैं और इस ऋणात्मक अंतराल को बंद करना (अर्थात्, वास्तविक वृद्धि घटाव संभाव्य वृद्धि) हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी अगली प्राथमिकता होगी संभाव्य वृद्धि पथ को आगे बढ़ाना।

17. तथापि, हमारी अर्थव्यवस्था के सामने कुछ मौलिक समस्याएँ हैं, जिनके समाधान के लिए अविलंब सुधारात्मक उपाय किये जाने आवश्यक हैं। समाज में यह सामान्य बोध है कि आरबीआई ब्याज दर को ऊँचा रख कर वृद्धि को कुंठित कर रहा है। यहाँ मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसका कारण आरबीआई का कार्य नहीं है, इसका कारण तो मुद्रास्फीति है, जिसके चलते प्रणाली में ब्याज दरें ऊँची हैं। और मुद्रास्फीति के नरम होने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाया जाना होगा। यदि हमें 9 प्रतिशत और उससे

अधिक वृद्धि-दर प्राप्त करनी हो,तो मुद्रास्फीति को 5 प्रतिशत से नीचे रहना होगा। उच्च मुद्रास्फीति हमारी विनिमय दर पर भी प्रभाव डालती है और सीएडी की समस्या को और अधिक गंभीर बना देती है। इससे जुडी समस्या है सोने के आयात की। भारत के निर्धन देश होने और उसके पास विदेशी मुद्रा का होना आवश्यक होने से 56 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य से अधिक का स्वर्ण आयात सीएडी को नियंत्रित रखने और और मुद्रास्फीति को नीचे लाने में मदद नहीं करेगा। जबकि सोने के आयात में थोड़ी नरमी आयी है, जिसका मुख्य कारण है सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा हाल में आरंभ किये गये कुछ उपाय, इसके साथ ही लोगों में यह जागरूकता लायी जानी है कि सोने का अधिक आयात किये जाने से देश को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सांस्कृतिक परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है और मैं प्रबंधन के क्षेत्र के छात्रों की इस तरुण ब्रिगेड से आशा रखता हूँ कि वे समाज की सोच में यह बदलाव लायें। मैं पुनः जोर दे कर कहना चाहता हूँ कि मुद्रा-स्थिरता का लक्ष्य केवल मुद्रास्फीति को नीचे ला कर और सीएडी को प्रबंधयोग्य सीमा में रख कर प्राप्त किया जा सकता है।

18. अब तक, वृद्धि का चालक घरेलू उपभोग रहा है, जिसके बाद निवेश का स्थान है, जिसका निधीयन अधिकांशतः घरेलू बचत के माध्यम से किया जाता था। लेकिन एक ऐसी अर्थव्यवस्था में, जिसमें निरंतर उच्च मुद्रास्फीति बनी रहे, लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति क्रमशः कम होती गयी है, जो हमारे निवेश को बाधित कर रही है। अतः हमें संभाव्य वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक विदेशी अंतर्वाह पर भरोसा करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में, यह आवश्यक है कि खुदरा, बैंकिंग, बीमा आदि जैसे क्षेत्रों में एफडीआइ को नियंत्रित करने वाली वर्तमान नीतियों की समीक्षा की जाये। वास्तव में, हम इस प्रकार की स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिसमें धन के प्राप्त होने पर अधिक सवाल किये जाते हैं, धन के बाहर जाते समय नहीं। हमें ऐसी नीतियाँ बनानी हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था में निधियों के आने को प्रेरित करें, जो आर्थिक वृद्धि में मददगार हो। सहवर्ती रूप से, हमें सामान्य नागरिकों के बीच बचत करने की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित करने का समर्थक वातावरण बनाना होगा।

जनांकिकी फायदों का उपयोग करना

19. भारत एक तरुण राष्ट्र है और हमारी आबादी भी युवा है। यह 'जनांकिकी लाभ', जिसने अतीत में हमारी मदद की थी, भविष्य में निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। तथापि, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के इस युग में हमें अत्यधिक कुशल मानव-पूँजी की आवश्यकता है, जो हमें अन्य राष्ट्रों की तुलना में बढ़त दे सके। इसके लिए, भारत को शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को काफी बढ़ाना आवश्यक होगा। शिक्षा की गुणवत्ता में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा, ताकि नवोन्मेष और उद्यम-वृत्ति का संवर्धन हो। अनुसंधान और निकास के क्षेत्र में संस्थाएँ स्थापित किये जाने के लिए अधिक निधियों का निवेश किये जाने की आवश्यकता होगी, जिसमें उत्पादकता में सुधार करने तथा कृषि, मझौले और लघु उद्योग, आदि जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा। इस बात को समझना महत्वपूर्ण है कि जब तक हम जनांकिकी लाभ को समुचित रूप से काम में लाने में समर्थ नहीं होंगे, तब तक यह जनांकिकी अभिशाप में बदल जा सकता है।

20. एक और फायदा, जो हमें हुआ है, वह यह है कि हमारी उत्पादकता और दक्षता का स्तर इतना नीचा है कि इसके लिए एक ही रास्ता बचा है कि यह ऊपर जाये। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास कौशल है, जिससे आप नौकरी-बाजार में जाने पर अच्छा कर सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, कुशल पेशेवर लोगों की माँग हमेशा से की जाती रही है और भविष्य में यह न केवल भारत जैसी वृद्धिशील अर्थव्यवस्था में, बल्कि विश्व-स्तर पर की जाती रहेगी।

बचे हुए मुद्दे और आगे बढ़ते हुए हम किस प्रकार उनका समाधान करेंगे?

21. हाल के समय में वृद्धि में गिरावट के लिए अनेक कारण बताये जाते हैं, जिनमें से कुछ वैश्विक हैं और कुछ घरेलू कारण हैं। सचमुच, वैश्विक कारक सुपरिचित हैं, जिनमें शामिल हैं वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट, जिसके बाद यूरो क्षेत्र संकट का स्थान है और हाल के समय में युएस फेड के परिमाणात्मक सौकर्य को क्रमशः कम किये जाने की युक्ति है। मेरा अधिक ध्यान यहाँ घरेलू मुद्दों पर केंद्रित है, क्योंकि ये हमारे नियंत्रण में हैं।

अभिशासन और नीतिगत मुद्दे

22. भारत अभी भी प्रमुख अभिशासन पैरामीटरों के संबंध में औसत से नीचे स्तर पर बना हुआ है, जैसाकि वर्ष 1996 से लेकर 2012 तक के लिए संकलित विश्व बैंक के विश्वव्यापी अभिशासन संकेतकों से पता चलता है। हमारे अभिशासन में

महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुए हैं (चार्ट 3)। स्पष्टतः इन पैरामीटरों में सुधार किये जाने की बहुत गुंजाइश है। हमारे समग्र अभिशासन और कारपोरेट अभिशासन, दोनों में सुधार की आवश्यकता है। वास्तव में, हमें सभी स्तरों पर- अस्पताल और शिक्षा संस्थाओं से ले कर राज्य-व्यवस्था, फर्मों, लाभ रहित संस्थाओं, बैंकिंग एवं वित्त, विनियम, भूमि अभिलेखों और यहाँ तक कि हमारे दैनंदिन जीवन में भी, बेहतर अभिशासन की आवश्यकता है।

प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना

23. हमें इस प्रकार की नीतियाँ बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके, यथा, वायु, जल, ऊर्जा और खनिज संसाधन।

आधारभूत संरचना के लिए निवेश को बढ़ाना

24. प्रत्येक विकसित अर्थव्यवस्था के पास विश्व-श्रेणी की आधारभूत संरचना है और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कुशल इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है, जो हमारे देश के लिए इस प्रकार की आधारभूत संरचना का सृजन कर सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या यह है कि जबकि विश्व-श्रेणी की आधारभूत संरचना के लिए माँग की जाती है, लोग सामान्यतः इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए रुपये खर्च करने में रुचि नहीं रखते हैं। हमारे समाज की इस मनोवृत्ति को बदला जाना होगा और लोगों को यह महसूस करना होगा कि जब तक ये बुनियादी सुविधाएँ स्वतःसमर्थ नहीं बन जातीं, तब तक आगे इस प्रकार की आधारभूत संरचना के लिए निवेश नहीं किया जा सकेगा। इस संदर्भ में, यह निश्चित है कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का कुछ त्याग करना होगा, लेकिन यह भी इसके समान ही महत्वपूर्ण है कि जो लोग विस्थापित होते हैं, उन्हें न्यायोचित और साम्यिक ढंग से क्षतिपूर्ति प्राप्त हो। आधारभूत संरचना के लिए निवेश में बढ़ोतरी करने और परियोजनाओं को उचित समय के भीतर कार्यान्वित करने से अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक प्रोत्साहन प्राप्त होगा और सर्वांगीण प्रगति होगी और विकास बढ़ेगा।

नवोन्मेष और उद्यमवृत्ति

25. भारत नवोन्मेष और उद्यमवृत्ति के क्षेत्र में पिछड़ता रहा है। हमें जीईडीआइ, जो एक लाभ रहित अनुसंधान एवं परामर्शी फर्म है, द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इंटरप्रेनियरशिप एंड डेवलपमेंट इंडेक्स, 2013 (जीईडीआइ) में 118 देशों में 89वें स्थान पर रखा गया है। 'डूइंग बिजनेस 2013 रिपोर्ट', जो विश्व बैंक ग्रुप के अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संचालित एक अध्ययन है, में भारत को उन 185 देशों के बीच 173वें स्थान पर रखा गया है, जिनका सर्वेक्षण 'व्यवसाय आरंभ करने' के मानदंड के आधार पर किया गया। जैसाकि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है, हमारी शिक्षा प्रणाली की काफी पुनर्संरचना करना आवश्यक है, जिससे कि यह नवोन्मेष और उद्यमवृत्ति का संवर्धन कर सके। देश में प्रबंधन शिक्षा के लिए एक प्रमुख संस्था के छात्रों के रूप में आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप में से अनेक छात्र अपनी उद्यमकर्ता रूपी ऊर्जा को उन्मुक्त कर सफल व्यवसाय-उद्यम स्थापित करने की ओर उन्मुख होंगे, न कि केवल पहले से स्थापित फर्मों में अपनी जीवनि-वृत्ति आरंभ करेंगे।

उद्यमवृत्ति का निधीयन

26. किसी प्रारंभिक उद्यम की एक प्रमुख चिंता होती है उसके निधीयन के बारे में। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि सेबी के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ) और विदेशी उद्यम पूँजी निवेशक (एफवीसीआइ), जो 2010 की तीसरी तिमाही में (जुलाई-सितंबर) वर्तमान बाजार मूल्य पर जीडीपी के लगभग 3.1 प्रतिशत तक पहुँच गयी थी, उसमें उसके बाद से गिरावट आनी आरंभ हो गयी (चार्ट 4)। इस प्रवृत्ति को उलटने की आवश्यकता है।

27. भारत जोखिम पूँजी के लिए आकर्षक गंतव्य स्थल के रूप में उभर रहा है। तथापि, इस बात की आवश्यकता है कि उद्यमियों को व्यवसाय की शुरुआत में प्रारंभिक प्रक्रम पर जोखिम पूँजी की उपलब्धता बढ़ा कर उद्यमकर्ता पारिस्थितिकी में और भी सुधार किया जाये। यही वह संदर्भ था, जिसमें योजना आयोग ने अक्तूबर 2011 में एंजेल इन्वेस्टमेंट और अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल के संबंध में श्री सुनील मित्रा[4] की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

28. सुनील मित्रा समिति का मानना है कि भारत की उद्यमकर्ता-वृद्धि को अधिक सहायक स्थितियों- एक उत्प्रेरक सरकारी और विनियामक वातावरण, पर्याप्त पूँजी प्रवाह (ऋण और इक्विटी, दोनों), व्यवसायों से और समाज से समर्थन और युक्तियुक्त प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उपलब्धता एवं

[4] समिति की रिपोर्ट planningcommission.nic.in/reports/genrep/rep_eco2708.pdf पर उपलब्ध है।

परामर्श- का सृजन करते हुए तेज गति प्रदान की जा सकती है। इन सिफारिशों को आने वाले दशक के भीतर देश में रोजगार और धन सृजन के रणनीतिक क्षेत्र में आगे ले जाने के महत्वपूर्ण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए समिति ने प्रस्ताव किया है कि इसमें समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय उद्यमवृत्ति मिशन को सौंपा जाये। समिति की सिफारिशों की विस्तृत जाँच किये जाने की आवश्यकता है और प्राथमिकता के आधार पर युक्तियुक्त कार्रवाई आरंभ की जानी है, ताकि नये उद्यमों को पूँजी-प्रवाह में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा सके।

व्यवसाय करने में सहूलियत

29. भारत को अभी भी एक समर्थक और प्रेरक व्यवसाय-वातावरण का सृजन करने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा। 'डूइंग बिजनेस 2013' रिपोर्ट के अनुसार हमें 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में 185 देशों में से 132वें स्थान पर रखा गया है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि व्यवसायों की यथार्थ आवश्यकताओं का समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे लोगों का उद्यमकर्ता उत्साह परिहार्य प्रक्रियात्मक जटिलताओं के चलते भंग न हो, एक कारगर संस्थागत ढाँचे का निर्माण किया जाये। मुझे निश्चय है कि सरकार और नीति-निर्माता इस मुद्दे से पूर्णतया अवगत हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

उत्पादकता बढ़ाना

30 वर्षों से न्यून उत्पादकता एक बाध्यता रही है, यह बाध्यता कृषि और उद्योग के मामले में अधिक रही, और शायद इससे कम सेवा क्षेत्र के मामले में थी। दृष्टांत के लिए, भारत चावल, गेहूँ, गन्ना और मूँगफली का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक (वर्ष 2010 में) है। तथापि, इन फसलों की उपज प्रमुख देशों की तुलना में कम है। इस बात की अविलंब आवश्यकता है कि इन सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ायी जाये, क्योंकि यह वृद्धि का महत्वपूर्ण चालक होता है।

31. मैं दृढ़तापूर्वक यह विश्वास करता हूँ कि बैंकिंग सेवाओं में उत्पादकता और दक्षता भारत में[5] सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए रक्षात्मक परकोटा का कार्य करेंगे। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में उत्पादकता और दक्षता के पैरामीटरों में निश्चयात्मक सुधार हुए हैं। तथापि, इस क्षेत्र में केवल परिचालन-दक्षता में बढ़ोतरी देखी गयी है और आबंटनीय दक्षता को क्षति पहुँची है, जिसके चलते समाज के सभी वर्गों को लाभ नहीं प्राप्त हुआ।

32. अर्थव्यवस्था इस समय जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उस पर विचार करते हुए इसमें कोई संदेह नहीं कि यही उपयुक्त समय है, जब भारतीय बैंकिंग में उत्पादकता बढ़ाने का बड़ा प्रयास किया जा सकता है। इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग उत्पादकता और दक्षता के समस्त प्रतिमान को अनुकूल बना कर उसे हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संरेखण में लाया जाये।

सरकार और आरबीआई द्वारा अब तक आरंभ किये गये उपाय

33. अब मैं सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा अब तक आरंभ किये गये हाल के उपायों में से कुछ के बारे में चर्चा करना करना चाहता हूँ। सितंबर 2012 के दूसरे सप्ताह से भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था में निवेश के माहौल को सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से अनेक नीतिगत उपायों की घोषणा की, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं, निवेश के संबंध में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति (सीसीआइ) का गठन, मल्टीब्रैंड रिटेल, उड्डयन एवं ब्राडकास्टिंग में एफडीआइ का उदारीकरण और बिजली, पेट्रोलियम एवं गैस, सड़क, कोयला, आदि में बड़े निवेश वाली परियोजनाओं की प्रगति को तेज करना। सरकार ने इन बड़ी राशियों वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में एक परियोजना अनुश्रवण दल का भी गठन किया है।

34. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विनिर्माण के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगी। सरकार का कोयला क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है और उसने प्राकृतिक गैस कीमत-निर्धारण नीति में परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव किया है। सरकार ने कुछ और क्षेत्रों में भी, जिनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रिफाइनिंग, सिंगल ब्रैंड रिटेल ट्रेडिंग, बेसिक और सेलुलर सेवाएँ, आस्ति-पुनर्निर्माण कंपनियाँ, आदि शामिल हैं, एफडीआइ मानदंडों को उदार बनाया है।

[5] चक्रवर्ती, के.सी. (2013), 'प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स इन इंडियन बैंकिंग इन दि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। अनुभव, मुद्दे और चुनौतियां', सितंबर http://rbi.org.in/Scripts/BS-ViewBulletin.aspx?Id=14410 पर उपलब्ध।

35. आर्थिक गुंजाइश बनाने के लिए वित्त मंत्री ने वर्ष 2013-14 के बजट में राजकोषीय घाटे को, जो पिछले वर्ष 5.2 प्रतिशत पर था, कम करके जीडीपी के 4.8 प्रतिशत पर लाने का प्रयास किया। बजट में यह भी प्रस्ताव किया गया कि आधारभूत संरचना निवेश को बढ़ावा देने के लिए किये गये उपक्रमणों को आगे भी जारी रखा जायेगा, जिसमें आधारभूत संरचना ऋण निधियों को प्रोत्साहन देना, उन आधारभूत संरचना कंपनियों को आइआइएफसीएल-एडीबी के माध्यम से ऋण में बढ़ोतरी करना, जो बांड बाजार में पहुँच प्राप्त करना चाहती हैं, वर्ष 2013-14 में कर-मुक्त बांडों की सकल अधिकतम सीमा को बढ़ा कर 50,000 करोड़ रुपये करना, सड़क क्षेत्र में वित्तीय तनाव, बढ़ी हुई निर्माण जोखिम और संविदा प्रबंध जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना, शामिल है। इसके अतिरिक्त, नये निवेश को आकृष्ट करने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति को तेज करने के लिए बड़ी राशि वाले नये निवेशों के लिए निवेश गुंजाइश की शुरुआत की गयी। यह उम्मीद की जाती है कि इससे लघु और मझौले उद्यमों को काफी मात्रा में अधिप्लव लाभ प्राप्त होगा।

36. सीएडी स्तर को वहनीय स्तर तक घटाने के लिए रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार ने विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ (i) स्वर्ण पर सीमा शुल्क में वृद्धि, (ii) सभी मनोनीत बैंकों/मनोनीत एजेंसियों को अनुदेश यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वर्ण आयात(किसी भी स्वरूप/ शुध्दता में जिसमें स्वर्ण सिक्के / ढ़ली हुई छडे का आयात शामिल हो)के प्रत्येक हिस्से का कम से कम एक पांचवां हिस्सा केवल निर्यात के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है तथा (iii) निवेशकों को स्वर्ण से आदत छुड़ाकर अन्य बचत लिखतों की ओर आकर्षित करने के लिए मुद्रास्फीति युक्त बांड जारी करना शामिल है।

37. प्रधानमंत्री का कार्यालय चुनिंदा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के सीएपीइएक्स और निवेश योजनाओं का अनुश्रवण वित्त वर्ष 12-13 से इस दृष्टि से करता आ रहा है कि अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़े और सीपीएसई का उपयोग आर्थिक वृद्धि को प्रेरित करने के लिए किया जाये।

बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियाँ

38. बैंकिंग क्षेत्र की ओर विशेष नजर डालते हुए, मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को वित्त प्रदान करते हुए देश की आर्थिक वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि आर्थिक गिरावट के बावजूद हमारी बैंकिंग प्रणाली पूँजी और लाभप्रदता की दृष्टि से स्पंदनशील बनी हुई है, हम विश्राम नहीं कर सकते हैं। जबकि बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता दबावग्रस्त है, यह स्थिति प्रबंधयोग्य है। तथापि, मैं इस तथ्य को आलोकित करना चाहता हूँ कि हमारे विश्लेषण के अनुसार, बैंकिंग प्रणाली में उच्चतर एनपीए होने का एक बड़ा कारण वैश्विक वित्तीय संकट के पूर्व विद्यमान सौम्य वातावरण में उधार के मानदंडों में कुछ शिथिलता होना है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था में एक अन्य अर्थहीन प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है और वह यह है कि कारपोरेट क्षेत्र और सरकार अत्यधिक सुविधाभोगी बन गये हैं। बैंकों को चाहिए कि वे अत्यधिक सुविधाभोगी कारपोरेटों को समझ-बूझ कर उधार दें। बैंक ऋण प्रमुख रूप से उत्पादक प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के वास्ते दिया जाता है और इसलिए लोगों को ऋण का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं करना चाहिए।

39. विनिर्दिष्ट रूप से, हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन, जोखिम प्रबंध सक्षमता और मानव पूँजी के संदर्भ में सुधार किये जाने की बहुत गुंजाइश है। वित्तीय संकट के प्रमुख कारणों में से एक कारण था बाजार प्रतिभागियों का लालच और अनैतिक प्रथाएँ। इतिहास इस बात का गवाह है कि एक अक्षम प्रणाली अनुशासनहीनता को जन्म देती है, जो बदले में, संसाधनों को बरबाद करने, आत्म-तुष्टि, धोखाधड़ियो, न्यून वृद्धि, आदि का कारण बनता है। हमारी बैंकिंग प्रणाली को यह सुनिश्चित करना है कि यह सुदक्ष बनी रहे और संपदा क्षेत्र के कार्यकलापों का समर्थन करती रहे।

छात्रों के लिए संदेश

40. मैं छात्रों को सलाह देने में सावधान रहता हूँ, क्योंकि आपकी पीढ़ी के लोग सलाह के प्रति अधिक ग्रहणशील नहीं होते। अतः, मैं आपको केवल कुछ सुझाव दूँगा। आपके लिए मैं तीन संदेश देना चाहूँगा, जो मैं हमेशा करता हूँ, जब कभी मुझे छात्रों के साथ संवाद करने का अवसर मिलता है। मेरा पहला संदेश यह है कि आपको 'तीसरी पीढ़ी की साक्षरता' प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जबकि पहली पीढ़ी की साक्षरता का संबंध किताबें पढ़ कर ज्ञान प्राप्त करने से है, दूसरी पीढ़ी की साक्षरता का संबंध कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी रखने से है। मुझे निश्चय है कि आप सभी पहली और दूसरी पीढ़ी की साक्षरता प्राप्त कर चुके हैं। तथापि, जिस तीसरी

पीढ़ी की साक्षरता के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वह है 'सूचना साक्षर' होना। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आपको हमेशा उन घटनाओं से अवगत रहना होगा, जो आपके इर्द-गिर्द घटती हैं। आप में हमेशा अधिक से अधिक सीखने की ललक होनी चाहिए और आपको ज्ञान प्राप्त करने तथा उसे आत्मसात करने के लिए निरंतर उत्सुक रहना चाहिए और अपने ज्ञान को अद्यतन बनाये रखना चाहिए। आपके लिए मेरा दूसरा संदेश यह है कि जीवन में कभी आत्मसंतुष्ट न बनें। सकारात्मक सोच रखें और आत्मसंतुष्टि से बचें। यह तो और भी महत्वपूर्ण है, यदि आप वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ आत्मसंतुष्टि के कुछ पलों का अनर्थकारी परिणाम हो सकता है। वास्तव में, जब मुझसे पूछा जाता है कि क्या आप चिंतित हैं, तो मैं कहता हूए कि ''हाँ, मैं चिंतित हूँ''। इस संबंध में आरबीआई के गवर्नर भी हमेशा चिंतित रहते हैं, क्योंकि वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले लोग और धन संबंधी कार्यवाही करने वाले लोग एक पल के लिए भी आत्मसंतुष्ट नहीं रह सकते। मेरा तीसरा और अंतिम संदेश यह है कि जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती और अपने पेशे में आपको कभी न कभी कुसमय का सामना करना पड़ सकता है। यह भी, कि जब कुसमय आता है, तब यह चारों ओर से आता है। इस अवधि के दौरान आप एकांत में रहें, निराश न हों और ईश्वर की प्रार्थना करें, क्योंकि सुसमय को पुनः आना ही होगा। यदि आप उपर्युक्त तीन संदेशों का अनुसरण करेंगे, तो आप अपने जीवन और पेशे में हमेशा सफल होंगे। इस संस्थान से जो ज्ञान आपने अर्जित किया है वह आपके लिए आपके पसंदीदा सभी क्षेत्रों में सफलता का द्वार खोलेगा।

समाहार

41. समाहार करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि अधिकांश देशों की तुलना में हमारी समस्या न केवल अधिक साधारण है, बल्कि हम उससे भली-भाँति अवगत भी हैं। हमारे पास बढ़ती आबादी है और इसलिए हम वृद्धि के आधार स्तर पर रहेंगे, चाहे जैसी भी स्थिति आये। इसलिए यह मुद्दा केवल वृद्धि को 'बनाये रखने' का नहीं है, बल्कि हमारी 'संभाव्य' वृद्धि दर पर बने रहने का है। मेरे विचार से, इस उच्च वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए उत्पादकता और दक्षता में बढ़ोतरी केंद्रविन्दु के रूप में है। हमें इस तथ्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि दूसरे लोग अपने हिस्से का काम वस्तुतः नहीं कर रहे हैं, न ही हमें अपना घर व्यवस्थित करने के पूर्व यह देखने के लिए रूक जाना चाहिए कि सब कुछ ठीक-ठाक है। परोपकार घर से शुरूहोता है, और इसलिए हमें वही करना चाहिए, जो हमारी क्षमता के भीतर हो, भले ही हमारे चतुर्दिक बाध्यताएँ हों। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता की माँग समाज की ओर से की जाती है और इसलिए अनुशासनहीनता के प्रति कठोर असहिष्णुता विकसित की जानी होगी।

42. मैं एक बार पुनः नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विश्वविद्यालय को और स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के संकाय सदस्य और छात्रों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक प्रासंगिक विषय पर मुझे अपने विचारों को साझा करने के लिए इस सम्मेलन में आमंत्रित किया। मुझे निश्चय है कि एनएमआइएमएस के तेजस्वी युवा छात्र उन मुद्दों पर मंथन करेंगे, जिन्हें मैंने आज उनके सामने प्रस्तुत किया है और इस बात पर विचार करेंगे कि भारत किस प्रकार आने वाले दिनों में अपना वृद्धि संवेग पुनः प्राप्त कर सकता है। भावी व्यवसाय प्रबंधकों और उद्योग के संभाव्य कप्तान के रूप में आप पूरे राष्ट्र की प्रत्याशाओं का बोझ वहन करते हैं। मुझे विश्वास है कि कठिन परिश्रम से हम विपत्तियों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होंगे और दूसरों की तुलना में उच्च वृद्धि के प्रक्षेप-पथ पर जल्दी लौटेंगे। मैं अमरीकी उपन्यासकार नोर रॉबर्ट्स के एक उद्धरण से अपनी बात समाप्त करूँगा, जो इस प्रकार है, ''यदि आप जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो वह आपको कभी नहीं मिलेगा। यदि आप कुछ पूछेंगे नहीं, तो उत्तर हमेशा नहीं में होगा। यदि आप आगे कदम नहीं बढ़ायेंगे, तो हमेशा उसी स्थान पर बने रहेंगे''।

43. मैं आपके सम्मेलन की और आपके भावी प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद !

अनुबंध ए: सारणियाँ

सारणी 1: प्रमुख समष्टिआर्थिक वैरिएबल

चरण	अवधि	औसत वृद्धि दर(%)		प्रतिशत में				
		जीडीपीएफसी (स्थिर मूल्य)	एनएनपीपीसी (स्थिर मूल्य)	निवेश दर (वर्तमान मूल्य)	बचत दर	संयुक्त जीएफडी (वर्तमान मूल्य)	सीएडी (वर्तमान मूल्य)	डब्लूपीआइ मुद्रास्फीति
I	1951-52 से 1979-80	3.5	1.3	14.5	13.4	n.a	-0.9	5.7*
II	1980-81 से 1993-94	5.3	2.9	21.2	19.5	7.9	-1.7	8.7
III	1994-95 से 2002-03	6.0	4.0	24.9	24.1	8.3	-0.6	5.9
IV	2003-04 से 2007-08	8.7	7.1	33.6	33.3	7.4	-0.3	5.3
V	2008-09 से 2012-13	7.2	5.2	35.7@	32.6	8.2	-3.0	7.6

* - 1953-54 और उसके बाद; @ - 2011-12 तक.

टिप्पणी : जीडीपीएफसी-कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद; एनएनपीपीसी- निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति; निवेश दर = सकल घरेलू पूँजी निर्माण (जीडीसीएफ) वर्तमान मूल्य पर/जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्य पर; बचत दर = सकल घरेलू बचत/जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्य पर; संयुक्त जीएफडी-केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का सकल राजकोषीय घाटा; सीएडी अनुपात = चालू खाता घाटा/जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्य पर

स्रोत : *केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), भारत सरकार और हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिकल्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय रिजर्व बैंक*

सारणी 2: क्षेत्रीय वृद्धि दरें और संरचनात्मक रूपांतरण

चरण	अवधि	औसत वार्षिक वृद्धि दर (%)			
		कारक लागत पर जीडीपी	कृषि	उद्योग	सेवाएँ
I	1951-52 से 1979-80	3.5	2.1 *(43.9)*	5.4 *(15.0)*	4.5 *(39.2)*
II	1980-81 से 1993-94	5.3	4.0 *(31.8)*	5.7 *(19.6)*	6.1 *(48.0)*
III	1994-95 से 2002-03	6.0	2.2 *(24.1)*	6.3 *(21.0)*	7.7 *(54.9)*
IV	2003-04 से 2007-08	8.7	4.9 *(18.4)*	8.8 *(20.3)*	9.8 *(61.3)*
V	2008-09 से 2012-13	7.2	2.9 *(14.5)*	5.4 *(19.9)*	8.8 *(65.6)*

कोष्ठक के आँकड़े कुल जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा इंगित करते हैं

स्रोत : *केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), भारत सरकार*

अनुबंध बी: चार्ट

चार्ट 1 : कारक लागत पर वास्तविक जीडीपी में भारत की वृद्धि

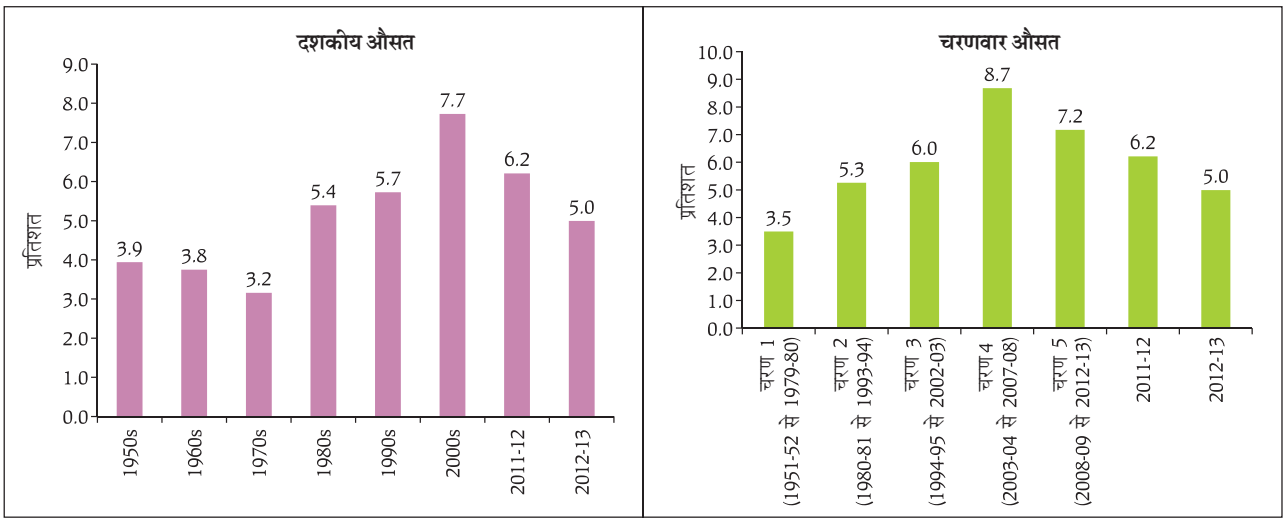

टिप्पणी : 1950 के दशक का संबंध वर्ष 1950-51 से 1960-61 तक है । 1960 के दशक का संबंध वर्ष 1961-62 से 1970-71 तक है, आदि

चार्ट 2 : विश्व जीडीपी में भारत का हिस्सा, जो क्रय शक्ति समता (पीपीपी) शर्तों पर आधारित है

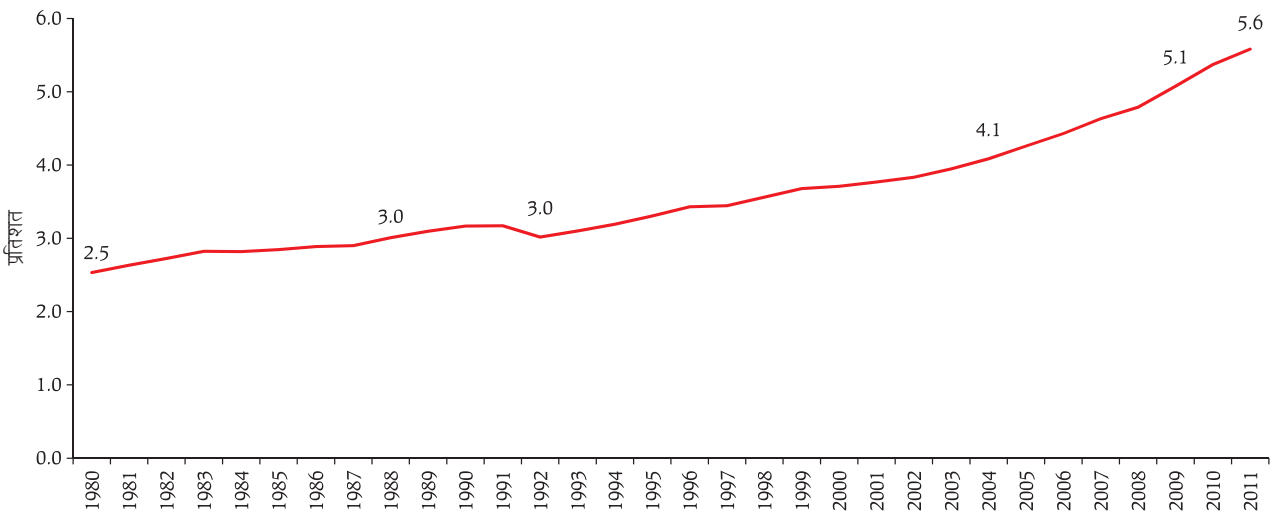

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डाटाबेस, अप्रैल 2013

चार्ट 3 : विश्वव्यापी अभिशासन संकेतक, 2012 के अनुसार अभिशासन संकेतक

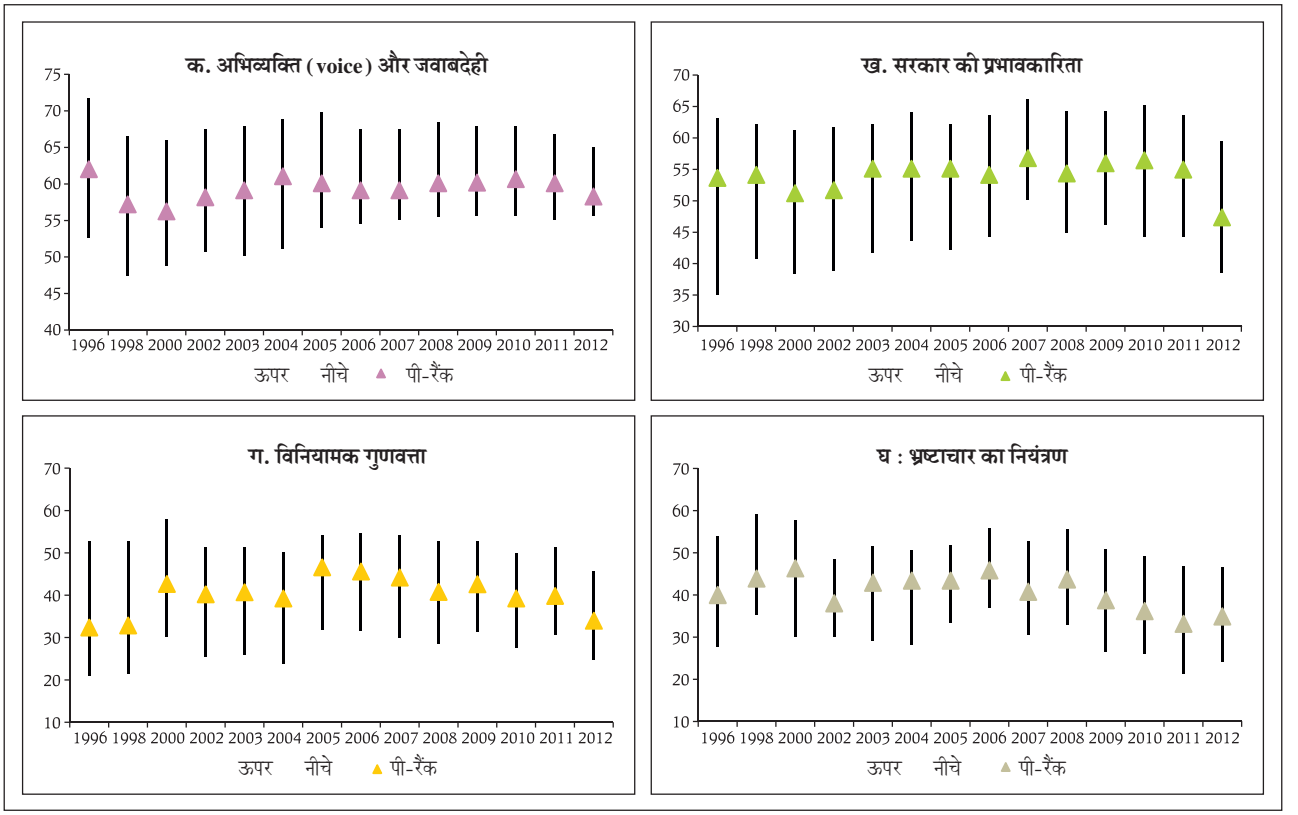

टिप्पणी :
पी-रैंक प्रतिशत रैंक सभी देशों के बीच (0 (न्यूनतम) से 100 (उच्चतम) रैंक की सीमा में
नीचे निचली सीमा विश्वास अंतराल का 90%, प्रतिशत रैंक के अर्थ में
ऊपर ऊपरी सीमा विश्वास अंतराल का 90%, प्रतिशत रैंक के अर्थ में

चार्ट 4 : वर्तमान बाजार मूल्य पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में उद्यम पूँजी निधियों (वीसीएफ) और विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों (एफवीसीआइ) के निवेश संबंधी ब्यौरे

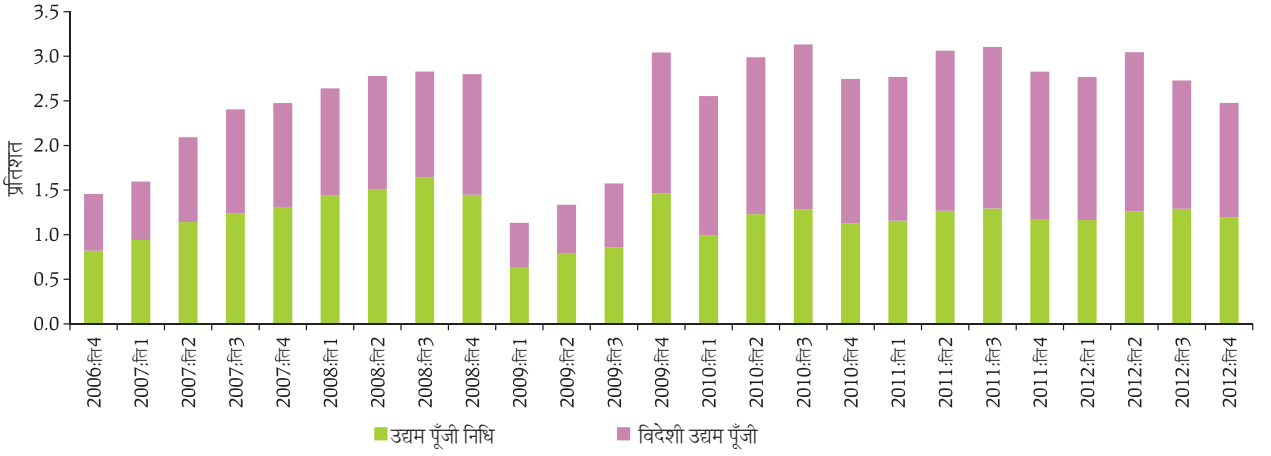

टिप्पणी : 2012 : ति4 का संबंध 31 दिसंबर 2012 को समाप्त तिमाही से है
स्रोत : सेबी, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन सिक्युरिटीज मार्केट, 2012